साप्ताहिक
Live not just breaTHE

MPHIN/2015/63220
MP/IDC1528/16-18

दि कार्मिक पोस्ट

वर्ष : 5, अंक : 31 (प्रति बुधवार), इन्दौर, 25 से 31 मार्च 2020 पेज : 4 कीमत : 3 रुपये

कोरोना के कहर का कोहराम

डॉ सोनल मेहता

आज क़रीब 568 reported केसेज़ हैं जो कल तक शायद 700 भी हो सकते हैं। इतना भयावह है ये. दूसरी बीमारियों या suicides या ऐक्सिडेंट्स से इसे compare नहीं कर सकते क्यूँकि वो सब या तो ठीक हो सकती हैं या रोकी जा सकती हैं या फिर फैलाव संख्यात्मक है गुणात्मक नहीं पर present नोवेल कोरोना वाइरस तो exponential गति से आगे बढ़ रहा है.

इन बीमारियों से निपटने की तीन approaches हैं. एक तो चाइना, नोर्थ कोरीआ , रशिया, हॉंगकॉंग, सिंगापुर, Israel और जर्मनी का है, जहां सरकार ने त्वरित और strict actions लिये तथा लोगों ने self discipline का esample पेश किया. दूसरा रास्ता इटली, US, UK का जहां लोगों ने इसे casually लिया और सरकार ने वक्त रहते सख़्त कदम नहीं उठाए तथा इसे लोगों के स्वविवेक पर छोड़ दिया. तीसरा रास्ता ईरान का है जो समय रहते इसकी भयावहता को नहीं समझ पाया. अब ये हमारे ऊपर है कि हम किस रास्ते को चुनना चाहते हैं. भारत के पास शुक्र है कि ये precedents हैं जिनसे हम सबक़ ले सकते है और एक और चीज़ जो प्लस है हमारे पास वो है response time इस आपदा को काउंटर करने का। समय रहते ये स्टेप्स इसलिए भी ज़रूरी हैं क्यूँकि यहाँ जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है और कई कई इलाक़ों में 2,80,000/sqkm जैसे मुंबई का धारावी इलाक़ा. ऐसे इलाक़ों में यदि Covid19 फैल गया तो फिर ईश्वर ही मालिक है. इस बीमारी का कोई इलाज नहीं social distancing के अलावा, क्यूँकि यदि ये स्टेज 3 मैं पहुँचा तो स्टेज 4 और स्टेज 5 में जान लेकर ही ख़त्म होगा। यदि रोक सकते हैं तो स्टेज 2 पर ही रोकना पड़ेगा. वाइरस फैलने के ग्राफ़ को नीचे से नीचे रखने की कोशिश करें हम सब और किसी भी तरह उसे ऊपर ना बढ़ने दें.

कुछ सुझाव जो गुजरते वक्त के साथ ज़रूरी होते जा रहे है

1) राजनीतिक और सामाजिक उपाय-

a) केंद्र, राज्य और केंद्र शासित राज्यों को मतभेद भुला कर एक धरातल पर आ कर एक ही दिशा में काम करना होगा.

b) Disaster Management Act 2005 के section 13 (relief in repayment of loans) और section 30 (power and functions of District Authority) को अमल में कड़ाई से लाना चाहिए .

c) सभी धर्म के नेताओं और उपदेशकों को कोरोना के issue पर sensitise करना होगा ताकि वो जनता को समझा सकें और जागरूक कर सकें। भारतीय समाज में ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है।

d) बूथ स्तर पर स्वयंसेवक तैयार करना. Ngo इसमें मदद कर सकते हैं. इससे लोगों का घर पर ही उनके बुलावे पर उचित दामों में रोज़मर्रा का सामान उपलब्ध कराया जा सके जिससे कम से कम लोगों का बाहर निकलना होगा।

2) अर्थव्यवस्था के लिए सुझाव

a) ये साल tax holiday घोषित किया जाए या फिर income ta& file करने की तारीख़ बढ़ायी जाए, GST suspend किया जाए, बिजली और पानी के बिल एक सीमा तक माफ़ किए जाएँ, सम्पत्ति कर माफ़ किया जाय.

b) store purchase rules का implementation हो

c) worst hit sectors के लिए bail out package घोषित किए जाएँ।

d) नोट छपाई का प्रतिशत बढ़ाया जाए और सरकारी लोन जो विभिन्न वैश्विक agencies देती हैं उसको भी बढ़ाया जाए।

e) एक अनुमान के मुताबिक़ बेरोज़गारी दर 9% से बढ़कर 23% तक हो सकती है. इसको ध्यान में रखते हुए individual और कम्पनी की EMI और लोन repayment समय बढ़ाया जाए .

3) स्वास्थ्य सुझाव-

a) Disaster Management Act 2005 ke तहत सभी ज़रूरी सामान लाया जाए

b) डिस्टिलरीज़ और केमिकल industries को sanitizers बनाने और उचित मूल्यों पर बाँटने को कहा जाए.

c) कपड़ा बनाने वाली industries को masks उपलब्ध कराने की कहा जाए.

d) Disposable linens, war footing par बनाए जाएँ.

e) Community centres, schools को quarantine wards में तबदील किया जाए अभी के लिए.

जैसे-जैसे समय बीतता जा रहा है, स्थिति गम्भीर होती जा रही है। कई conspiracy theories circulate हो रहीं है वाइरस की उत्पत्ति के विषय में जिन पर ध्यान ना देकर बचाव को हो महत्व दें क्यूँकि 'सावधानी में ही सुरक्षा है'।

अंग्रेज़ी कहावत है, ' Desparate times need Desparate actions' और ये Desparate times ही तो है.

जय विश्व! जय भारत!
डॉ सोनल मेहता

जहां पानी ही अशुद्ध हो वहां कोरोना वायरस से बचने के लिए हाथ धोना कितना सुरक्षित है?

नावेल कोरोनावायरस (कोविड-19) से जूझने के मामले में भारत की वाहवाही हो रही है। हाथ धुलाई को लेकर चलाए जा रहे जागरूकता अभियान और उसमें बड़ी हस्तियों को भी शामिल करने जैसे प्रयासों की काफी चर्चा हो रही है। इस बीच एक चिंता सामने आ रही है कि माध्यम आय वर्ग वाले देश जैसे अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन और एशिया के साथ भारत में साफ पानी की सुविधा कम लोगों को ही उपलब्ध है।

विश्वभर में निम्न अज्ड माध्यम आय वाले देश के 180 करोड़ लोग बेहद प्रदूषित पानी का उपयोग करते हैं। इन आंकड़ों का खुलासा ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड इंटरनेशनल हेल्थ नामक पत्रिका में 2014 में छपे एक शोध से हुआ। इन देशों में लोग पानी में मौजूद सूक्ष्म प्रदूषण से ग्रस्त हैं और दक्षिणी विश्व में गंभीर किस्म का प्रदूषण पानी में पाया जाता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्टकहती है कि पूरे विश्व में तकरीबन 190 करोड़ आबादी द्वारा उपयोग किया जाने वाला जल पीने, साफ सफाई और दूसरे कामों के लायक ही नहीं होता, और इस पानी का स्त्रोत मुख्यत: भूजल है।

भारत में 6,50,000 गांवों में सफलतापूर्वक 1.64 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया है। सेंटर फ़ॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा किए गए शोध के अनुसार, मल उपचार की तकनीक सभी शौचालयों के लिए सुरक्षित नहीं है।

अफ्रीकन देशों जिनमें नाइजीरिया, यूगांडा और केन्या शामिल हैं, में ऐसी ही स्थिति देखी का सकती है। सारे देशों के पास साफ सफाई के दुरुस्त इंतजाम नहीं हैं। खुले में शौच और शौचालय में मल उपचार की अच्छी तकनीक न होने की वजह से बिना उपचारित या आधा-अधूरा उपचारित मल पानी के स्त्रोतों में जा मिलता है।

इससे भूजल और मिट्टी दोनों प्रदूषित होती है। इन देशों में ग्रामीण और कस्बाई आबादी भूजल या खुले जल स्त्रोतों पर निर्भर है जहां स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं है।

जलजनित रोगों में डायरिया सबसे अधिक जान लेने वाला रोग बना हुआ है जिसकी वजह से 60 प्रतिशत मृत्यु जो रही है। यह आंकड़ा पूर्व स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने लोक सभा में एक सवाल के जवाब में वर्ष 2018 में पेश किया था।

हैजा, टाइफाइड और वायरल हैपेटाइटिस पानी से होने वाले अन्य रोग हैं जिससे अक्सर ग्रामीण आबादी प्रभावित होती है। पानी से होने वाली बीमारियों से होने वाली मौतों का प्रमुख कारण डायरिया है।

केंद्रीय स्वास्थ्य ब्यूरो द्वारा जारी वार्षिक प्रकाशन 2019 के नेशनल हेल्थ प्रोफाइल के अनुसार, 2017 में 1,362 और 2018 में 1,450 लोगों की इस बीमारी की वजह से मौत हो गई थी।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पूर्व अतिरिक्त निदेशक दीपांकर साहा के अनुसार, भारत के ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में हाथ धोने का मतलब दूषित पानी का उपयोग करना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत में भूजल में प्रवेश करने वाले जैविक प्रदूषक तत्व आज के समय में एक प्रमुख चिंता का विषय है।

हालांकि, यदि हाथ धोने में साबुन का इस्तेमाल हो रहा है तो यह पानी में मौजूद जीवाणु को खत्म करने में सक्षम है। साफ पानी को लोगों तक पहुंचा कर कोविड-19 जैसे बीमारियों से पुख्ता तरीके से लड़ा जा सकता है।

उत्तर बंगाल में क्यों बढ़ रही है गिद्धों की संख्या?

पिछले दो दशक से उत्तर बंगाल में गिद्ध दिखने बंद हो गए थे, लेकिन पिछले दिनों जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग के सीमा पर बागराकोट में 200 से ज्यादा गिद्ध देखे गए, तो वन विभाग के अधिकारियों की बांछें खिल गईं।

बागराकोट में हिमालयन ग्रिफॉन और ह्वाइट-बैक्ड दोनों प्रजाति के गिद्ध दिखे हैं। 20 साल बाद इन गिद्धों की बागराकोट में वापसी को वन विभाग के अधिकारी अच्छा संकेत मान रहे हैं और उनका कहना है कि आनेवाले दिनों में इनकी तादाद बढ़ेगी।

जालदापाड़ा वाइल्डलाइफ के डीएफओ कुमार विमल ने डाउन टू अर्थ को बताया कि वन क्षेत्र के संरक्षण के चलते वन्य प्राणियों की संख्या में इजाफा हुआ है। इनकी संख्या बढ़ने से गिद्धों को आसानी से भोजन मिल जा रहा है। इस से उन्हें इस क्षेत्र की आबोहवा रहने लायक लग रही है। यही वजह है कि वे यहां नजर आने लगे हैं।

पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से लोकसभा में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, भारत में अभी करीब 19 हजार गिद्ध हैं। तीन दशक पहले इनकी संख्या चार करोड़ थी। जानकारों के मुताबिक, पशुओं के दर्द निवारण के लिए डिक्टोफेनाक नाम की दवा का बेतहाशा इस्तेमाल किया जाता है, जो पक्षियों के लिए विषैला होता है। जब ये पशु मरते हैं, तो गिद्ध उन्हें खाते हैं, जिस

कारण डिक्टोफेनाक उनके शरीर में प्रवेश कर जाता है और उनकी मौत हो जाती है।

पिछले साल गुवाहाटी में एक मृत मवेशी को खा लेने से 33 गिद्धों की मौत हो गई थी जबकि 30 से ज्यादा गिद्धों को मौके से गंभीर हालत में बरामद कर इलाज कराया गया था।

भारत सरकार ने इस दवा के इस्तेमाल पर 2006 में ही प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन इसके बावजूद चोरी-छिपे इसका इस्तेमाल हो रहा है।

कुमार विमल ने बताया कि उत्तर बंगाल में इस दवा का इस्तेमाल बंद करने के लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया गया है। गिद्धों का लौटना साबित करता है कि जागरूकता अभियान का असर हो रहा है।

उन्होंने कहा, हमलोगों ने पशु चिकित्सकों से लेकर पशुपालकों व आम लोगों को लगातार जागरूक किया कि वे डिक्टोफेनाक की जगह दूसरी दवाइयों का इस्तेमाल करें। जागरूकता अभियान से इस दवाई के इस्तेमाल में कमी आई है। हम इसकी भी पड़ताल कर रहे हैं कि और क्या वजहें हैं कि वे लौटे हैं। इससे हमें गिद्धों के रहने के अनुकूल आबोहवा देने में मदद मिलेगी।

कोरोना लाइव ट्रैकर

भारत में अब तक सामने आ चुके हैं 562 मामले; जबकि 9 लोगों की हो चुकी है मृत्यु

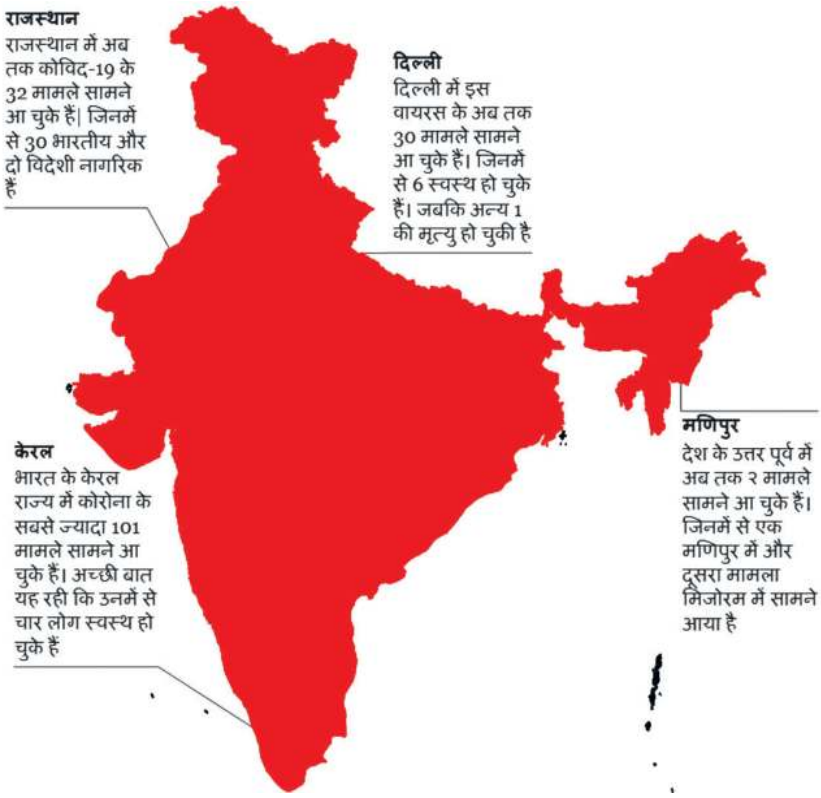

भारत में कोरोना वायरस (कोविद - 19) के मामले दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। अब तक देश में करीब 562 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। जिनमें 43 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। इस सं मण से अब तक 9 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। जबकि 41 मामले ऐसे हैं, जिसमें या तो मरीज ठीक हो चुके हैं, या फिर अपने देश वापस जा चुके हैं। देश में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य केरल है जहां अब तक 101 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। जबकि महाराष्ट्र में 98 और दिल्ली में 30 मामले सामने आ चुके हैं।

कोरोना संक्रमण- चिड़ियाघरों में जानवरों को खाना-पानी पहुंचाने का आदेश

कोरोनावायरस संक्रमण से बचाव के लिए देशभर में लॉक डाउन और धारा 144 के तहत कर्फ्यू की स्थिति है। ऐसे में सिर्फ आम लोगों को ही नहीं बल्कि चिड़ियाघरों में मौजूद पालतू जंतुओं को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बंदी के चलते ज्यादातर बुनियादी सुविधाओं के सामान उन तक नहीं पहुंच रहे हैं। इसे देखते हुए देश के सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को आदेश दिया गया है कि जरूरी सेवाओं के तहत चिड़ियाघर के

पालतू जीवों के खाने-पीने व स्वास्थ्य की देखभाल का इंतजाम सुनिश्चित किया जाए।

यह आदेश डॉक्टर सदस्य सचिव एसपी यादव की ओर से 23 मार्च, 2019 को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधीन केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने देश के सभी राज्यों के मुख्य सचिव को दिया है। आदेश में कहा गया है कि सभी राज्यों को मुख्य वन्यजीव संरक्षक व चिड़ियाघर के इंचार्ज पालतू जीवों को पेयजल, खाना और स्वास्थ्य देखभाल की सभी चीजें जीवों तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। बुनियादी सुविधाओं के लिए चिड़ियाघरों को कफर्यू से बाहर रखा जाए।

जारी आदेश की प्रति में कहा गया है कि चिड़ियाघर के जीव कर्फ्यू या लॉक डाउन के चलते काफी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में उनकी न सिर्फ सेहत की देखभाल की जाए बल्कि बुनियादी जरूरतों की चीजें भी समय-समय पर पहुंचाई जाएं।

केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने 2017-18 में देशभर के चिड़ियाघरों का वर्गीकरण किया था। इसके अलावा प्राधिकरण की 2018 रिपोर्ट के मुताबिक देश में कुल 160 चिड़ियाघर को मान्यता मिली हुई है। वहीं, बीते वर्ष 40 चिड़ियाघरों को मानकों के उल्लंघन पर कारण बताओ नोटिस भी दिया गया था।

इस वक्त देश के कुल 160 चिड़ियाघरों में 17 बड़े चिड़ियाघर, 25 मध्यम स्तरीय, 35 लघु और 83 अत्यंत छोटे चिड़ियाघर हैं। इनमें 16 रेस्क्यू सेंटर भी शामिल हैं।

भारत की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा कोरोना महामारी का भविष्य- विश्व स्वास्थ्य संगठन

23 मार्च को जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित एक प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के आपात कार्यक्रम निदेशक माइक रेयान ने कहा कि वायरस की प्रसार गति इस बात पर निर्भर करेगी कि भारत जैसी घनी आबादी वाला देश किस आक्रामक तरीके से इस महामारी से निपटता है। माइक रेयान ने कहा, भारत ने दो खामोश लेकिन बहुत खतरनाक हत्यारे, चेचक और पोलियो को खत्म करने में बहुत बड़ी भूमिका निभा कर दुनिया को एक शानदार उपहार दिया है। भारत में जबरदस्त क्षमताएं हैं। रेयान ने आगे कहा कि इन दोनों बीमारियों को खत्म करने में मजबूत निगरानी नेटवर्क की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही और अब सन्दिग्ध कोविड-19 मरीजों को खोजने में इसी निगरानी नेटवर्क के इस्तेमाल किए जाने की आवश्यकता है।

डब्लूएचओ पैनल मानता है कि आक्रामक परीक्षण द्वारा कोरोना सन्दिग्धों की तलाश करना ही इस महामारी के खिलाफ महत्वपूर्ण हथियार है। यदि भारत या कोई भी अन्य देश परीक्षण किटों की कमी का सामना कर रहा है तो उसे डब्ल्यूएचओ के दिशानिर्देशों को अपनाना चाहिए कि कैसे भविष्य के अनुसार परीक्षण को प्राथमिकता दी जाए।

भारत में टेस्ट (परीक्षण) प्रणाली एक कमजोर क्षेत्र रहा है, क्योंकि इसने अब तक केवल 18,000 से अधिक नमूनों का ही परीक्षण किया है जब कई अन्य देश प्रति सप्ताह कई हजार परीक्षण कर रहे हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के महानिदेशक बलराम भार्गव ने कई मौकों पर कहा है कि भारत अंधाधुंध परीक्षण में विश्वास नहीं करता है। रेयान ने जोर देकर कहा कि आक्रामक परीक्षण का मतलब अंधाधुंध परीक्षण नहीं है। रेयान ने कहा, हम यह नहीं कह रहे हैं कि हर किसी का परीक्षण किया जाना चाहिए। लेकिन हम कहते हैं कि जिनका अंतरराष्ट्रीय यात्रा या संपर्क का इतिहास है, उनके साथ ही निमोनिया के रोगियों का भी (जिनमें लक्षण हो जरूरी नहीं है) परीक्षण होना चाहिए।

23 मार्च को लगभग 20 राज्यों में पूर्ण या आंशिक लॉकडाउन की घोषणा के साथ भारत में शटडाउन हो चुका है। कुछ अन्य देशों ने भी लोगों की आवाजाही को कड़ाई से प्रतिबंधित किया है। रेयान ने कहा, लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित करना या लोगों को घर पर रहने के लिए कहना महामारी की तीव्रता को कम करेगा। लेकिन अगर हमें इस महामारी से बाहर निकलना है, तो हमें सन्दिग्धों की पहचान बढ़ानी होगी और सकारात्मक मामलों के लिए आइसोलेशन (सबसे अलग रखना) सुनिश्चित करना होगा। परीक्षण सबसे महत्वपूर्ण है। आने वाले हफ्तों में यह काम और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा।

कोई देश कब तक अपने लोगों को घर के भीतर बंद कर सकता है? डब्ल्यूएचओ के अधिकारियों ने कहा कि ये एक ऐसा अभ्यास है, जिसे निरंतर बनाए रखना कठिन है।

रेयान ने कहा, शटडाउन केवल महामारी के दबाव या तनाव को कम कर सकता है। हमने इबोला और पोलियो के प्रकोप में देखा है। देशों को वायरस के खिलाफ कदम उठाना ही होगा। सिंगापुर और दक्षिण कोरिया ने ऐसा ही किया। सरकारों को सब कुछ बंद नहीं करना पड़ा। स्कूलों और लोगों की आवाजाही को ले कर कुछ रणनीतिक निर्णय लिए गए। ये देश कुछ कठोर उपायों के बिना आगे बढ़ने में सक्षम रहे हैं। वे सन्दिग्ध मरीजों की तलाश करने जैसे हथियारों की बदौलत इस महामारी पर रोक लगा पाने में सक्षम रहे हैं।

शटडाउन वायरस को खत्म करने के कम असरकारी और तात्कालिक उपाय है. इसके संपूर्ण खात्मे के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य उपकरण किट, परीक्षण जैसे महत्वपूर्ण उपाय भी करने होंगे।

शटडाउन कारगर समाधान नहीं

यदि किट की कमी हैं, तो हमारे पास इसे ले कर दिशा-निर्देश हैं कि कैसे परीक्षण को प्राथमिकता दी जाए और महामारी प्रसार के चरण के आधार पर पीडित देश हमारे निर्देश का अनुपालन करें। मारिया वॉन ने कहा, हर देश को यह देखना चाहिए कि परीक्षण किट का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए ताकि हम कारगर तरीके से वायरस के खिलाफ लड़ सकें।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सोनल मेहता केलिए प्रतीक्षा ग्राफिक्स, 127 देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर (म.प्र.) से मुद्रित एवं 209-बी शहनाई रेसीडेंसी-2 कनाड़िया रोड इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक: डॉ. सोनल मेहता फोन : 0731-2595008 Mail.sonal12mehta@yahoo.co.in 9755040008